

**विभिन्न न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मुकदमों**

4835 श्री राजेंद्र कुमार शर्मा : क्या बिधि, न्याय और कम्पनी कार्य यती यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न निचले न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में तीन वर्षों तथा अधिक समय से अनिर्णीत पड़े मुकदमों की संख्या कितनी है ?

बिधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : तारीख 31-12-1978 को देश के उच्च न्यायालयों में ऐसे मामलों की संख्या, जो तीन वर्ष तथा इससे अधिक अवधि से लम्बित है, 193534 थी ।

देश के विभिन्न निचले न्यायालयों में तीन वर्ष तथा इससे अधिक अवधि से लम्बित मामलों की संख्या उपलब्ध नहीं है । तथापि, तारीख 30-6-1978 को विभिन्न निचले न्यायालयों में लम्बित कुल मामलों की संख्या संलग्न विवरण में बताई गई है ।

**विवरण**

30-6-1978 को निचले न्यायालयों में लम्बित मामले —

आपराधिक मामले —

| सेशन न्यायालय | लम्बित मामलों की संख्या |
|---------------|-------------------------|
| मूल           | 68975                   |
| पुनरीक्षण     | 21104                   |
| अपील          | 43184                   |
| <b>कुल</b>    | <b>133263</b>           |

| 1                   | 2              |
|---------------------|----------------|
| मजिस्ट्रेट न्यायालय |                |
| पुलिस चालान         | 2757897        |
| परिवाद-मामले        | 1786328        |
| <b>कुल</b>          | <b>4544225</b> |
| सिविल मामले —       |                |
| मूल पक्ष            |                |
| नियमित वाद          | 1417002        |
| प्रकीर्ण मामले      | 1214196        |
| <b>कुल</b>          | <b>2631198</b> |
| अपील पक्ष           |                |
| नियमित अपीलों       | 141156         |
| प्रकीर्ण अपीलों     | 51862          |
| <b>कुल</b>          | <b>193018</b>  |
| <b>कुल जोड़</b>     | <b>7501704</b> |

**स्थानीय फिल्मों को सहायता देने सम्बन्धी योजना**

4836. श्री हरगोविन्द शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय फिल्मों बनाने के काम को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता देने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को अलग-अलग कितनी धनराशि दी गई और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उमका उपयोग नहीं किया गया तो सरकार ने उमका उपयोग करने हेतु क्या निदेश दिए हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण झाडवाणी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

#### Survey in Andhra Coast

4897. SHRI K. SURYANARAYANA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Oil and Natural Gas Commission has conducted the preliminary survey in Andhra Coast regarding the presence of oil and the report was sent to Singapore for further examination and formulation; and

(b) if so, the details of the report and the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI NARSINGH YADAV) : (a) ONGC had conducted reconnaissance geophysical survey in Andhra coast off Vishakhapatnam—Madras during February to April, 1978. The geophysical data collected during this survey was sent to Singapore for its processing. The processed data has since been received by ONGC.

(b) The interpretation of the data by ONGC's scientists is in progress. A preliminary study of the data shows the possibility of presence of structures favourable for accumulation of hydrocarbons in relatively deeper waters in the offshore Godavari-Krishna area. Additional Geophysical survey is planned by ONGC during 1979 to delineate the structures and depending on the results of the survey, ONGC proposes to take up drilling during the later part of 1979/early 1980.

**विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल का उत्तरी बंगाल में सिलीगुड़ी को बिजली की सप्लाई पर प्रभाव**

4838 श्री राजनारायण : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विद्युत् बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल विद्युत् जाने से सिलीगुड़ी पर जो उत्तरी बंगाल का सबसे बड़ा नगर है, बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सिलीगुड़ी का बरौनी से 10 मेगावाट विद्युत् सप्लाई की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां विद्युत् की कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और विद्युत् कर्मचारियों की मांगे क्या हैं और उन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० राम स्वप्न) :**

(क) और (ख). बिहार राज्य बिजली बोर्ड मामान्यतया पश्चिम बंगाल को उत्तर बंगाल में स्थित दलकोला उप केन्द्र पर 10 मेगावाट विद्युत् सप्लाई करता है । बिहार राज्य बिजली बोर्ड के कामगारों की हड़ताल के दौरान पारेषण लाइनों की तोड़फोड़ के कारण कुछ दिन तक उत्तर बंगाल की विद्युत् सप्लाई प्रभावित रही । बोर्ड से लाइनों की मरम्मत की और यथा संभव कम समय में विद्युत् की सप्लाई बहाल कर दी ।

(ग) हड़ताल 18 मार्च, 1979 को वापस ले ली गई थी । कामगारों की मांगों पर गौर करने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है ।